which appeared in he 'Current' of the 15th March, 1986 wherein it has been stated that flesh trade is going on a very high scale with headquarters in Delhi;

(b) if so, what are the details in this regard; and

(c) what action Government have taken or propose to take in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS AND WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT (SHRIMATI MARGARET ALVA): (a) to (c) Yes, Sir. The article published in the 'Current' of 15th March, 1986 relates to a particular case of attempted kidnapping of a Bangladeshi women to Pakistan. The F.I.R. was registered on 18-2-1986 under section 366/34 of the Indian Penal Code. Two persons have been arrested in this case. The case has been challaned on 8-3-1986 and is at present under scrutiny in the prosecution branch of Delhi Administration.

बिहार में नेत्र सुधार संगठनों को सरकारी अनुदान

738. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में सरकार ने वार्षिक अनुदान के रूप में विभिन्न नेत्र सुधार संगठनों आदि को अलग-अलग कितनी धन-राशि दी है ;

(ख) इन अनुदानों को प्राप्त करने वाले संगठनों की संख्या कितनी है ;

(ग) क्या सरकार ने यह पता लगाने के लिए इन संस्थानों द्वारा किए जा रहे कार्य का मूल्यांकन किया है कि उन्हें दिये गये अनुदान का उनके द्वारा वास्तव में सदुपयोग किया जाता है ;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान उन विदेशी संस्थानों के नाम क्या-क्या हैं जिन्होंने इन संस्थानों को अथवा भारत सरकार को इस कार्य के लिए सहायता दी है ?

परिवार कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) से (घ) राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम राज्य सरकारों द्वारा एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में चलाया जा रहा है और नेत्र परिचर्या संगठनों को सीधे कोई केन्द्रीय सहायता नहीं दी जाती है । स्वयंसेवी संगठन ग्रामीण क्षेत्रों में लगाये नेत्र शिविरों में किए गये आपरेशन के लिए 60 रुपये प्रति आपरेशन की दर से सहायता-अनुदान के पात्र होते हैं और उनको ये अनुदान राज्य सरकार द्वारा उसे दिए गये धन में से स्वीकृत किए जाते हैं। बिहार सरकार को गत तीन वर्षों के दौरान इस कार्यक्रम के अन्तर्गत दिए गये सहायता अनुदान की रकम नीचे दी गई है :—

(रुपये लाखों में)

वर्ष	दी गई धन राशि
1983–84	46.56
1984–85	54.68
1985–86	21.42

बिहार में पिछले तीन वर्षों के दौरान किए गये मोतियाबिन्द के आपरेशनों की संख्या नीचे दी गई है :—

वर्ष	किए गये मोतिया-बिन्द आपरेशन
1983–84	59,802
1984–85	62,988
1985–86 (फरवरी 86 तक)	36,742

(ङ) भारत सरकार को उन विदेशी संगठनों की जानकारी नहीं है जो इन संगठनों को सहायता दे रहे हैं ।

राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम के अधीन निम्नलिखित सेवाओं के विकास के लिए भारत सरकार को डानिडा से विदेशी सहायता मिल रही है :—

1. निगरानी और मूल्यांकन
2. राज्य मुख्यालय में नेत्र चिकित्सा कक्ष
3. केन्द्रीय/जिला मोबाइल यूनिटें
4. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए उपकरण
5. स्वास्थ्य शिक्षा सामग्री

उपर्युक्त मदों पर किया गया खर्च इस कार्यक्रम के लिए रखे गये योजना प्रावधानों में से पूरा किया जाता है और डानिडा द्वारा इसकी वार्षिक प्रतिपूर्ति की जाती है ।

सतना से सीटों का कोटा

739. **श्री प्यारेलाल खंडेलवाल** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार वाराणसी एक्सप्रेस और हावड़ा मेल में सतना से कुछ सीटों के कोटे का आरक्षण करने का विचार रखती है ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : सतना स्टेशन को वाराणसी एक्सप्रेस और हावड़ा मेल गाड़ियों में निम्नलिखित कोटा प्रदान किया गया है :—

गाड़ियां	पहला दर्जा	दूसरा दर्जा
27 डाउन वाराणसी एक्सप्रेस	—	2 सीटें
28 अप वाराणसी एक्सप्रेस	—	बम्बई के लिए 3 शायिकाएं सूरत के लिए एक शायिका
3 अप कलकत्ता-	2 शायिकाएं	7 शायिकाएं
4 डाउन बम्बई-कलकत्ता मेल	3 शायिकाएं	7 शायिकाएं

इसके अलावा सतना को 1-6-1986 से 28 अप वाराणसी एक्सप्रेस में पहले दर्जे की दो शायिकाओं का कोटा आबंटित किया जा रहा है ।

दिल्ली-राझुरा-जगदलपुर रेलवे लिंक का सर्वेक्षण

740. **श्री प्यारेलाल खंडेलवाल** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली-राझुरा-जगदलपुर रेल लिंक के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) क्या यह सर्वेक्षण पूरा हो चुका है;

(ग) इस रेल मार्ग का निर्माण कार्य कब से प्रारंभ होने की संभावना है; और

(घ) क्या सरकार इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि यह एक आदिवासी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, इस लाइन के निर्माण को प्राथमिकता देने का विचार रखती है ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) और (ख) 1973-74 में सर्वेक्षण किया गया था । सर्वेक्षण को अद्यतन करने का काम अब शुरू किया गया है ।

(ग) और (घ) सर्वेक्षण पूरा हो जाने पर आगे कार्रवाई की जायेगी जो परियोजना के वित्तीय फलितार्थ और संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगी ।

परासिया-छिंदवाड़ा मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदला जाना

741. **श्री प्यारेलाल खंडेलवाल** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परासिया-छिंदवाड़ा मीटर-लाइन को बड़ी लाइन में बदलने की सरकार की कोई योजना है;